रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73 REGISTERED No. D.(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 18, 1978/ कार्तिक 27, 1900
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 1978/KARTIKA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1978

का०आ० 3313.—निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो चुका है कि जून, 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 220-सौसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अंडनामदेव राजाराम कोरडे, सिविल लाईन सौसर, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग को यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अंडनामदेव राजाराम कोरडे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०वि०स०/220/77]

वी० नागसुब्रमेनियम, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 6th September, 1978

S.O. 3313.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri And. Namdev Rajaram Korde, Civil Lines, Sausar, *District Chhindwara (Madhya Pradesh)*, who was a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly from 220-Sausar held in June, 1977 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder,

And whereas, the said candidate even after the due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri And. Namdev Rajaram Korde to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/220/77]

T. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1978

का०आ० 3314.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 30-सुलतान की बैटरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वजहावत्ता भारथन, पुत्र वोलान मुथान्गा, डाकघर नूलपूझा, जिला कोझीकोड (केरल राज्य) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वजहावत्ता भारथन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० केरल-वि०स०/30/77

ORDER

New Delhi, the 20th October, 1978

S.O. 3314.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vazhavatta Bharathan, S/o Volan Muthanga, P.O. Noolpuzha, District Kozhikode (Kerala State), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in March, 1977 from 30-Sultan's Battery constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vazhavatta Bharathan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/30/77]

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1978

का० आ० 3315.—निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो चुका है कि जून, 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए हरियाणा 69-बवानी खेड़ा (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सिंह, ग्राम व डा० बारसी, तह० बवानी खेड़ा, जिला भिवानी (हरियाणा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग को यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० हरि० वि०स०/69/77]

टी० नागरत्नम, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th October, 1978

S.O. 3315.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Singh, Village and P.O. Barsi, Tehsil Bawani Khera, District Bhiwani (Haryana who was a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly from 69 Bawani Khera (SC) held in June, 1977 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice, has not given any satisfactory reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-LA/69/77]

T. NAGARATHNAM, Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1978

का०आ० 3316.—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जे० माथन को, श्री एस० रंगराजन के स्थान पर, एतद्द्वारा 12 नवम्बर, 1978 से 24 जुलाई, 1980 तक भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा०सं० 81(1)-बीमा II-77]

शिव दयाल रहेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Division)

New Delhi, the 4th November, 1978

S.O. 3316.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri J. Matthan as Chairman of the Life Insurance Corporation of India vice Shri S. Rangarajan, with effect from the 12th November, 1978 to the 24th July, 1980.

[F. No. 81(1)-Ins. II/77]

S. D. RAHEJA, Under Secy.

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1978

का० आ० 3317.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन इण्डियन एक्सचेंज लिमिटेड अमृतसर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक-हित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 10 अगस्त, 1978 से 9 अगस्त, 1979 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएं ।

[सिविल संख्या 12(19)-आई०टी/78]

के० एस० मैथ्यू, उप सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Supplies and Cooperation)

New Delhi, the 21st October, 1978

S.O. 3317.—The Central Government, in consultation with Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Indian Exchange Ltd., Amritsar and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 10th August 1978 to 9th August 1979 (both days inclusive) in respect of forward confraces in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(19)-IT/78]

K. S. MATHEW, Dy. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1978

का०आ० 3318.—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-2, खंड 3, उपखंड (2) में 8 जून, 1978 को प्रकाशित इस मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 377 (ई) आई डी आर ए/21/1/78-पटसन में क्रमांक 9 तथा 19 की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां की जायेंगी ।

"9. अध्यक्ष,
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,
बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

19. वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार उद्योग भवन, नई दिल्ली में पटसन से बने माल के निर्यात से संबंधित कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव ।"

[फा सं० 21/1/78-जूट]

एन०एस० वैद्यनाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd November, 1978

S.O. 3318.—In this Ministry's Order No. S.O. 377(E)/IDRA/21/1/78-Jute published in the Gazette of India Extra-ordinary of the 8th June, 1978, in Part II, Section 3, Sub-section (ii), the entries appearing at serial Numbers 9 and 19 shall be delcted and substituted by the following :—

"9. Chairman,
Industrial Finance Corporation of India.
Bank of Baroda Building,
Parliament Street,
New Delhi.

19. Joint Secretary dealing with export of jute goods in the Ministry of Commerce,
Government of India,
Udyog Bhavan,
New Delhi."

[F. No. 21/1/78-Jute]

N. S. VAIDYANATHAN, Jt. Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1978

का० आ० 3319.—उत्प्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का 7) खंड-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय पासपोर्ट व उत्प्रवास कार्यालय, चण्डीगढ़ के जन-सम्पर्क अधिकारी, श्री टी० आर० आनन्द को अपने काम के अतिरिक्त तत्काल से अमृतसर हवाई अड्डे पर उत्प्रवासी संरक्षक भी नियुक्त करती है ।

[संख्या-सीपीईओ/31/78]

एस० सिवास्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 18th September, 1978

S.O. 3319.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Emigration Act, 1922 (7 of 1922), the Central Government hereby appoints Shri T.R. Anand, Public Relations Officer, Regional Passport and Emigration Office, Chandigarh to be Protector of Emigrants for the Amritsar Airport in addtion to this own duties with immdiate effect.

[No. C.P.E.O./31/78]

S. SIVASWAMI, Under Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम, विभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1978

का०आ० 3320.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप न० जी० जी० एस-VII से जी०जी०एस० I तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जी० जी० एस VII से जी०जी० एस-I तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका: गांधीनगर

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए	आरई सेन्टीयर
उवारसद . . .	1109/1	0	03	75
	1107	0	06	75
सेरथा . . .	722	0	03	75
	719	0	04	50

[सं० 12016/4/78-प्रोड०I]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICAL & FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 30th October, 1978

S.O. 3320.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S. VII to G.G.S. I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powrs conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-9 ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS VII to GGS I

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Uvarsad . . .	1109/1	0	03	75
	1107	0	06	75
Sertha . . .	722	0	03	75
	719	0	04	50

[No. 12016/4/78-Prod. I]

का० आ० 3321.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० सोभासण -36 से डब्लू एच आई-सोभासण-10 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकतर अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० सोभाषण 36 से डब्लू एच आई सोभासण 10 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाणा

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेन्टीयर
कुकरा	318/पी	0	38	16
	322	0	03	00

[सं० 12016/4/78-प्रो०]

S.O. 3321.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Sobhasan-36 to WHI Sobhasan-10 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara-9 ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquisition of R.O.U. from well No. Sobhasan—36 to W.H.I. Sobhasan 10.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kakus . . .	318/P	0	38	16
	322	0	03	00

[No. 12016/4/78-Prod.]

का०आ० 3322.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० डी० एस-बी० एफ० एफ० से जी० जी० एस०-I तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों का बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

डी० एस - बी० एफ० एफ० से जी० जी० एस-I तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य: गुजरात जिला: खेडा तालुका: मातर

गांव	सर्वे० नं०	हक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
नवागाम	110	0	14	78
	109	0	06	70
	108	0	04	05
	107	0	02	55
	105	0	05	88
	104	0	15	50
	कार्ट ट्रैक	0	16	05
	660	0	05	70
	657	0	11	55
	655	0	04	95
	653	0	10	20
	651	0	03	30
	650	0	08	70
	671/2	0	06	00
	671/1	0	03	37
	693	0	03	45
	कार्ट ट्रेड	0	03	45
	688	0	06	45
	689/1	0	06	75
	690	0	05	85
	692/1	0	09	90
	कार्ट ट्रैक	0	02	00
	740/1	0	02	00

[सं० 12016/8/78-प्रो०]

स०म० य० नदीम, अवर सचिव

SO. 3322.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from D.S. BFF to G.G.S. 1 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers confered by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of his notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Contruction & Mainteance Division, Makarpura Road, Vadodara—9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a leagal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from D.S. BFF to GGS I

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Nawagam . .	110	0	14	78
	109	0	06	70
	108	0	04	05

1	2	3	4	5
	107	0	02	55
	105	0	05	88
	104	0	15	50
	Cart track	0	16	05
	660	0	05	70
	657	0	14	55
	655	0	04	95
	653	0	10	20
	651	0	03	30
	650	0	08	70
	671/2	0	06	00
	671/1	0	03	37
	693	0	03	45
	Cart track	0	03	45
	688	0	06	45
	689/1	0	06	75
	690	0	05	85
	692/1	0	09	90
	Cart track	0	02	00
	740/1	0	02	00

[No. 12016/8/78-Prod.]

S.M.Y. NADEEM, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1978

का०आ० 3323.—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) की धारा 17 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री के० एच० चेनानी को एतद्द्वारा 16-8-1978 के पूर्वाह्न से सहायक भुगतान आयुक्त के पद पर नियुक्त करती है ।

[सं० 11023/17/78-सी०ए०]

जी०वी० जी० रामन, उप-सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 30th September, 1978

S.O. 3323.—In exercise of the power conferred under sub-Section (2) of Section 17 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973) the Central Government hereby appoints Shri K. H. Chainani, as Assistant Commissioner of Payments w.e.f. the fore-noon of 16-8-1978.

[No. 11023|17|78-CA]

G. V. G. RAMAN, Dy.Secy.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1978

का०आ० 3324.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 3153, तारीख 28 अगस्त, 1976 द्वारा, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 7225.00 एकड़ (लगभग) या 2923.81 हैक्टेयर (लगभग) माप की भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और उक्त भूमि की बावत, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 अगस्त, 1978 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार ऐसी भूमि को या ऐसी भूमि में के किन्हीं अधिकारों को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी ।

अनुसूची

जयंती खंड

जयंती कोयला क्षेत्र

ड्रा० सं० ध राज्य 16/76
तारीख 1-3-76
(जिसमें पूर्वेक्षण के लिये अधिसूचित भूमियां वर्णित हैं)

क्रम सं०	ग्राम	ग्राम सं०	अंचल	उप-खण्ड	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कालाझारिया	1	जामतारा	जामतारा	संथाल परगना		भाग
2.	गिरा	467	करन	देवघर	,,		,,
3.	बेमुजानर	468	,,	,,	,,		,,
4.	खुरखुरिया	469	,,	,,	,,		,,
5.	भण्डारे	470	,,	,,	,,		,,
6.	धास्को	481	,,	,,	,,		,,
7.	खपरशाद	482	,,	,,	,,		पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	खरजोरी	483	करन	देवघर	संथाल परगना		भाग
9.	काश्रो	539	,,	,,			,,
10.	बांसजोरा	540	,,	,,	,,		पूर्ण
11.	महुग्रातनर	541	,,	,,	,,		भाग
12.	सिमरा	553	,,	,,	,,		,,
13.	जगाडीह	554	,,	,,	,,		,,
14.	विगवाद	557	,,	,,	,,		,,
15.	वादिया	558	,,	,,	,,		पूर्ण
16.	हर्नी	559	,,	,,	,,		भाग
17.	सागरमांगा	592	,,	,,	,,		,,
18.	बासकुपी	594	,,	,,	,,		,,
19.	कालीबंध	595	,,	,,	,,		पूर्ण
20.	मिश्रा	596	,,	,,	,,		पूर्ण
21.	नागादरी	597	,,	,,	,,		भाग
22.	मोरजविहा	598	,,	,,	,,		,,
23.	बर्नमार	600	,,	,,	,,		,,
24.	सिरसिया	601	,,	,,	,,		पूर्ण
25.	बिराजपुर	602	,,	,,	,,		,,
26.	धनियावीह	603	,,	,,	,,		भाग
27.	काल्हो	604	,,	,,	,,		पूर्ण
28.	पहाड़वाहा या मदनकेटा	605	,,	,,	,,		भाग
29.	काठमिरखी	607	,,	,,	,,		,,
30.	गोरमारा	610	,,	,,	,,		,,
31.	बीरनगरिया	611	,,	,,	,,		पूर्ण
32.	चोवकियारी	618	,,	,,	,,		भाग
33.	गन्डुवा	619	,,	,,	,,		पूर्ण
34.	सिबातपर	620	,,	,,	,,		,,
35.	सोमबाक	621	,,	,,	,,		भाग
36.	केनाबरिया	622	,,	,,	,,		,,
37	रानीडी	640	,,	,,	,,		,,

कुल क्षेत्रफल : 7225.00 एकड़ (लगभग)
या 2923.81 हैक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन :

ए–बी लाइन पिपरा, बेजुतानर, खूरखुरिया और भण्डारी ग्रामों से होकर जाती है ।

बी–सी लाइन देवघर उपखण्ड के भण्डारी, काश्रो, महुग्रातनर, सिमरा, जगाडीह, विगवाद, नागादरी, मोरविहा, बर्नमार, ग्रामों, जामतारा उपखण्ड के कालाझरिया तथा देवघर उपखण्ड के केनाबरिया और रानीडीह ग्रामों से होकर जाती है ।

सी–डी लाइन रानीडीह, सोनाबाक और चोवकियारी ग्रामों से होकर जाती है ।

डी–ई लाइन उस नदी की मध्य रेखा, जो चोवकियारी और मानीयातानर ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा है, चौवकियारी और जमदाबार, चौवकियारी और ग्रासनवानी, बीरनगरिया और जसोबांध, बीरनगरिया और कोईराकी, बीरनगरिया और चेकियाजोरी ग्रामों की या मान्य सीमा तथा बीरनगरिया और गोरमारा ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है ।

ई–एफ लाइन जोरमारा, काठमिरसी और सागरमांगा ग्रामों से होकर जाती है ।

एफ–जी लाइन बाधदारा नदी की (जो बासकुपी और सिलबरिया वादिया और नवाडीह ग्रामों की सामान्य सीमा है तथा वादिया और हर्नी ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा है) आंशिक मध्य रेखा के साथ साथ जाती है ।

जी–ए लाइन हर्नी, काश्रो, खरजोरी और पिपरा ग्रामों से होकर जाती है और प्रारम्भ बिन्दु "ए" पर मिलती है ।

टिप्पण :—एच–ग्राई–जे–के–एल–एम और एच के परिबद्ध प्रभाग को छोड़कर, जो बासकुपी, धनियाडीह ग्रामों से होकर, धनियावीह और पहाड़वाहा या मदनकेटा ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ और तत्पश्चात् सागरमांगा ग्राम से होकर जाती है ।

[फा० सं० 19/39/76-सी०ई०एल]
एस० ग्रार० ए० रिजवी, निदेशक

New Delhi, the 4th November, 1978

S.O. 3324.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 3153 of 28th August, 76, under sub-section (i) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 7225.00 acres (approximately) or 2923.81 hect. (approximately) in the locality specified in the Schedule appended hereto :

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 28th August, 1978, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

SCHEDULE

Jayanti Block

Jayanti Coalfield

Drg. No. Rev. /16/76
Dated 1-3-76
(Showing lands notified for prospecting).

Sl. No.	Village	Village number	Anchal	Sub-Division	District	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kalajharia	1	Jamtara	Jamtara	Santhal Pargana		Part
2.	Pipra	467	Karan	Deogarh	,,		,,
3.	Baijutam	468	,,	,,	,,		,,
4.	Khurkhuriya	469	,,	,,	,,		,,
5.	Bhandaro	470	,,	,,	,,		,,
6.	Ghasko	481	,,	,,	,,		,,
7.	Khamarbad	482	,,	,,	,,		Full
8.	Kharjori	483	,,	,,	,,		Part
9.	Kao	539	,,	,,	,,		,,
10.	Bansjora	540	,,	,,	,,		Full
11.	Manuatanr	541	,,	,,	,,		Part
12.	Simra	553	,,	,,	,,		,,
13.	Jagadih	554	,,	,,	,,		,,
14.	Digbad	557	,,	,,	,,		,,
15.	Badiya	558	,,	,,	,,		Full
16.	Harni	559	,,	,,	,,		Part
17.	Sagarbhanga	592	,,	,,	,,		,,
18.	Baskupi	594	,,	,,	,,		,,
19.	Kalibandh	595	,,	,,	,,		Full
20.	Misra	596	,,	,,	,,		,,
21.	Nagadari	597	,,	,,	,,		Part
22.	Bhorandiha	598	,,	,,	,,		,,
23.	Burbshar	600	,,	,,	,,		,,
24.	Sirsiya	601	,,	,,	,,		Full
25.	Birajpur	602	,,	,,	,,		,,
26.	Dhaniyadih	603	,,	,,	,,		Part
27.	Kalho	604	,,	,,	,,		Full
28.	Pahardaha or Madanketa	605	,,	,,	,,		Part
29.	Kathmirkhi	607	,,	,,	,,		,,
30.	Gormara	610	,,	,,	,,		,,
31.	Birangariya	611	,,	,,	,,		Full
32.	Chobkiyari	618	,,	,,	,,		Part
33.	Ganduba	619	,,	,,	,,		Full
34.	Sivatanr	620	,,	,,	,,		,,
35.	Somabank	621	,,	,,	,,		Part
36.	Kenabariya	622	,,	,,	,,		,,
37.	Ranidi	640	,,	,,	,,		,,

Total area : 7225.00 acres (approx.)
or 2932.81 hect. (approx.)

BOUNDARY DESCRIPTION :

A B . . . line passes through villages Pipra, Baijutanr, Khurkhuriya and Bhandaro.

B-C . . . line passes through villages Bhandaro, Ghasko, Mahuatanr, Simra, Jagadih, Digbad, Nagadari, Bhorandiha, Burbshar of Deoghar Sub-division, Kalajharia of Jamtara Sub-division and Kenabariya & Ranidih of Deogarh Sub-division.

C-D . . . line passes through villages Ranidih, Sonabank, Chobkiyari.

D-E . . . line passes along the central line of the River which forms part common boundary with the villages of Chobkiyari and Naniyatanr, common boundary with the villages of Chobkiyari & Jamdabar, Chobkiyari and Asanbani, Chandiajori, part common boundary of villages Birangariya and Gormara.

E-F . . . line passes through villages Gormara, Kathmirkhi & Sagarbhanga.

F-G . . . line passes along the part Central line of Baghdara Nadi (which forms common boundary with the villages of Baskupi and Tilberiya, Badiya & Nawadih and forms part common boundary of villages Badiya and Harni).

G-A . . . line passes through villages Harni, Kao, Kharijari and Pipra and meets at starting point 'A'.

Note :—Excluding the portion bounded by H-I-J-K-L-M-N-and H which passes through villages Baskupi, Dhaniyadih, along the part common boundary of villages Dhaniyadih & Pahardana or Madankata through village Pahardaha and Kathmirkhi along the part common boundary of villages Sagarbhanga & Kashitanr then through village Sagarbhanga.

[No. 19(39)76-CEL]

S. R. A. RIZVI, Director

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय

(होम्योपैथिक डेस्क)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1978

का०आ० 3325—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय सूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में उड़ीसा से संबंधित मद 13 और उसकी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"राजस्थान :

13क. राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल, जयपुर।	होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा।	डी०एच०एम०एस०	1969 से 1973 तक

तमिलनाडु :

13ख. तमिलनाडु होम्योपैथिक परिषद्, मद्रास।	होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा।	डी०एच०एम० एस०	1973-1974 के दौरान।"

[सं० वी०-27021/1/78-होम्यो०]

के० बी० पिल्लै, उप-सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Homoeopathic Desk)

New Delhi, the 4th November, 1978

S.O. 3325.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:

In the said Schedule, after item 13, relating to Orissa and the entries thereto, the following items and the entries shall be inserted, namely :—

"Rajasthan :

13 A. Rajasthan Homoeopathic Medical College and Hospital, Jaipur.	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D.H.M.S.	from 1969 to 1973

Tamil Nadu :

13 B. Tamil Nadu Homoeopathic Council, Madras.	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D.H.M.S.	during 1973-74".

[No. V-27021/1/78- Homoeo]

K.B. PILLAI, Dy. Decy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1978

का०आ० 3326—अतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, संचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द कर दिया है जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं ।

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय की उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

अत: अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :—

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन किस पद पर स्थायी है	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के किस पद पर है	भारतीय खाद्य निगम की स्थानान्तरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री पदम सिंह	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	1-3-69
2.	श्री अरविंद सरकार	गोदाम लिपिक	गोदाम लिपिक	1-3-69
3.	श्री निखिल राजन घोष	चौकीदार	चौकीदार	1-3-69
4.	श्री रतन बहादुर सनवार	—वही—	—वही—	1-3-69
5.	श्री साधन कुमार दे	—वही—	—वही—	1-3-69
6.	श्री सत्य रंजन बिसवास	—वही—	—वही—	1-3-69
7.	श्री राम सरण पासवान	—वही—	—वही—	1-3-69
8.	श्री मो० सुलेमान खान	—वही—	—वही—	1-3-69
9.	श्री राम देव प्रसाद	—	गोदाम लिपिक	1-3-69
10.	श्री परिचन साव	स्टिचर	स्टिचर	1-3-69
11.	श्री श्याम बाबू यादव	—	चौकीदार	1-3-69
12.	श्री इन्द्रकान्त झा	—	—वही—	1-3-69
13.	श्री महेन्द्र झा	चौकीदार	—वही—	1-3-69
14.	श्री पी० दास गुप्त	गुण निरीक्षक	गुण निरीक्षक	1-3-69
15.	श्री हबीबुर रहमान	—	चौकीदार	1-3-69

[फाइल सं० 52/14/74-एफ०सी० 3-/वाल्य 6]
बख्शी राम, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 28th October, 1978

S. O. 3326.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India.

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporations of India as required by the proviso to sub-Section (I) of Section 12A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them.

Sl. No.	Name of the Officer/ employees	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to the FCI
1	2	3	4	5
1.	Sh. Padam Singh	Jr. Godown Keeper	Sr. Godown Keeper	1-3-69
2.	Sh. Arabinda Sarkar	Godown Clerk	Godown Clerk	1-3-69
3.	Sh. Nikhil Rajan Ghosh	Watchman	Watchman	1-3-69
4.	Sh. Ratan Bahadur Sanwar	Do.	Do.	1-3-69
5.	Sh. Sadhan Kr. Dey	Do.	Do.	1-3-69
6.	Sh. Satya Ranjan Biswas	Do.	Do.	1-3-69
7.	Sh. Ram Saran Paswan	Do.	Do.	1-3-69
8.	Sh. Md. Suleman Khan	Do.	Do.	1-3-69
9.	Sh. Ram Deo Prasad	—	Godown Clerk	1-3-69
10.	Sh. Parichan Sao	Stitcher	Stitcher	1-3-69
11.	Sh. Shyam Babu Jadav	—	Watchman	1-3-69
12.	Sh. Indra Kant Jha	—	Do.	1-3-69
13.	Sh. Mahendra Jha	Watchman	Do.	1-3-69
14.	Sh. P. Das Gupta	Quality Inspector	Quality Inspector	1-3-69
15.	Sh. Habibur Rahaman.	—	Watchman	1-3-69

[No. 52/14/74-FC. III (Vol. VI)]
BAKHSHI RAM, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1978

आदेश

का० आ० 3327.—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट के बारे में मैसर्स मंगलौर हार्बर प्रोजेक्ट, पनाम्बुर (अब नया मंगलौर पत्तन) के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एफ० एल० एफ० अल्वारस होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायानिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मंगलौर हार्बर प्रोजेक्ट पनाम्बुर (अब नया मंगलौर पत्तन) के प्रबन्धतन्त्र की श्री एम० के० चन्दप्पा, ड्राइवर, को 10 अक्तूबर, 1973 से छंटनी करने की कार्रवाई न्यायोचित है; यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।"

[संख्या एल०-45012(1)/70-डी०4-ए०]
नन्द लाल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 24th October, 1978

S.O. 3327.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Mangalore Harbour Project Panambur (now New Mangalore Port) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers confered by Section 7A and clause(d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri F.L.F. Alveres shall be the Presiding Officer with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tibunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Mangalore Harbour Project, Panambur (now New Mangalore Port) in retrenching Shri M. K. Chandappa, driver, with effect from 10th October, 1973 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[No. L-45012(1)/77-D.IV(A)]
NAND LAL, Desk Officer

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1978

का०आ० 3328.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात उन सरकारी सेवकों को जो मैसर्स हिन्दुस्तान टैलीप्रिंटर्स, गुईंडी, मद्रास में प्रतिनियुक्ति पर है और जिनके नाम इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदानिधान दिखाये जायेंगे;

(2) इस छूट के होते हुए, भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधायें प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिये वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ;

(3) छूट प्राप्त विधि के लिये यदि कोई अभिदाय पहले ही किये जा चुके हों तो वे वापिस नहीं किये जायेंगे ;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी:—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950, द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रख गये थे या नहीं; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गये उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने, के संबंध में अधिनियम की उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों में से किसी का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाये या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना ।

अनुसूची

क्रम सं०	नाम	पदाभिधान	छूट की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री के० सी० भूपति	पर्यवेक्षक	30-11-1975 से 29-11-78
2.	श्री ए० जयरामन	पर्यवेक्षक	30-11-75 से 29-11-1978
3.	श्री एस० चर्चिल	पर्यवेक्षक	30-11-75 से 29-11-78
4.	श्री वी० सोक्कालिंगम	नक्शानवीस श्रेणी-II	30-11-1975 से 29-11-78
5.	श्री आई० चिन्नास्वामी	कनिष्ठ इंजीनियर	30-11-75 से 29-11-78
6.	श्री वेगुण्डापति	नक्शानवीस श्रेणी-2	30-11-75 से 29-11-78
7.	श्री एच० डी० टोके	टेलीप्रिंटर तकनीकज्ञ	1-12-77 से 29-11-78

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट की मंजूरी के लिए प्रार्थना पत्र देर से प्राप्त हुआ। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि कारखाने के कर्मचारी छूट के पात्र हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस० 38014/42/78-एच० आई०]

एस० एस० सहस्रानामन, उप सचिव

New Delhi, the 4th November, 1978

S.O. 3328.—*In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the Government servants, who are on deputation with Messers Hindustan Teleprinters, Guindy, Madras and whose names are specified in the Schedule annexed hereto from the operation of the said Act for the periods specified in the corresponding entries in column 4 of the aforesaid Schedule.*

2. The above exemption is subject to the following conditions namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees ;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period : or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under the notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

SCHEDULE

Sl. No.	Name	Designation	Period of exemption
1	2	3	4
1	Shri K. C. Bhoopathy	Supervisor	30-11-1975 to 29-11-1978
2.	Shri A. Jayaraman	Supervisor	30-11-1975 to 29-11-1978
3.	Shri S. Churchill	Supervisor	30-11-1975 to 29-11-1978
4.	Shri G. Sokkalingam	Draughtsman Gr. II	30-11-1975 to 29-11-1978
5.	Shri I. Chinnaswamy	Junior Engineer	30-11-1975 to 29-11-1978
6.	Shri Vaigundapathy	Draughtsman Gr. II	30-11-1975 to 29-11-1978
7.	Shri H. D. Toke	Teleprinter Technician	1-12-1977 to 29-11-1978

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemptions in this case, as the request for exemption was received late. However, it is certified that the employees are eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/42/78-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1978

का०आ० 3329.—भारतीय गोदी श्रमिक विनियम, 1948 के विनियम 26 के अनुसरण में तथा भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1528 तारीख 2 मई, 1977 का अधिग्रहण करते हुये, केन्द्रीय सरकार, फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र, आफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सायन, बम्बई-400022 (डी०डी०) के महानिदेशक को उक्त विनियमनों के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी के रूप में नामित करती है।

[सं० एस०-17013/1/78-फैक्ट]

वी० चन्द्र मौलि, निदेशक

New Delhi, the 6th November, 1978

S.O. 3329.—In pursuance of regulation 26 of the Indian Dock Labourers Regulations, 1948, and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 1528, dated the 2nd May, 1977, the Central Government hereby nominates the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Off Eastern Express Highway, Sion, Bombay-400022 (DD) as the authority for the purposes of the said regulations.

[No. S-17013/1/78-FAC]

V. CHANDRA MOWLI, Director.

आदेश

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1978

का०आ० 3330.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में विजय बैंक लिमिटेड, बंगलौर के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एफ० एस० एफ० अल्वेरस होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या विजय बैंक लिमिटेड, बंगलौर के प्रबन्धतंत्र की, विजय बैंक एम्प्लाएज एसोसिएशन के प्रेसीडेंट, श्री एच० सुब्बाया शेट्टी को, बैंक के प्रशासकीय कार्यालय से केम्पागोयदा रोड शाखा बंगलौर में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो श्री एच० सुब्बाया शेट्टी किस अनुतोष के हकदार हैं?"

[सं० एल-12011/101/78-डी० 2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 4th November, 1978

S.O. 3330.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Vijaya Bank Ltd., Bangalore and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7-A read with clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal the Presiding Officer of which shall be Shri F.L.F. Alvares with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the proposed action of the management of Vijaya Bank Ltd. Bangalore to transfer Shri H. Subbayya Shetty, President of Vijaya Bank Employees' Association from Administrative Office of the Bank to the Kempakgowda Road Branch Bangalore is justified? If not, to what relief is Shri H. Subbayya Shetty is entitled?"

[No. L-12011/101/78-D. II. A.]

आदेश

का०आ० 3331.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री आर०सी० इसरानी होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या भारतीय स्टेट बैंक, अहमदाबाद के प्रबन्धतंत्र की, कुमारी सुलोचना सी० दोशी, लिपिक, अहमदाबाद में बैंक की भद्रा शाखा, को 24 फरवरी, 1976 से बैंक की सेवा से बरखास्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल० 12012/111/77-डी० 2 ए०]

ORDER

S.O. 3331.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7-A read with clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with headquarters at Ahmedabad, the Presiding Officer of which shall be Shri R. C. Israni and refers the said dispute for adjudication to the said Central Government Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the State Bank of India, Ahmedabad in discharging Miss Sulochana G. Doshi, Clerk Bhadra Branch of the Bank in Ahmedabad from the Banks service w.e.f. 24-2-1976 is justified? If not, to what relief is the workman entitlded?"

[No. L-12012/111/77-D. II. A.]

New Delhi, the 6th November, 1978

S.O. 3332.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of the Corporation Bank Ltd., Madras and Shri A. Sankaran Nair over non-grant of additional sick leave which was received by the Central Government on the 30-10-1978.

BEFORE THIRU K. SELVARATNAM, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS.

(Constituted by the Central Government)

Monday, the 16th day of October, 1978

Industrial Dispute No. 22 of 1978

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of the Corporation Bank Limited, Mangalore).

BETWEEN

The workmen represented by
The Organising Secretary,
Corporation Bank Employees Union,
No. 135, Moore Street, Madras.

AND

The General Manager (Personnel) Corporation Bank Limited, Administrative Office, P.B. No. 88, Mangalore.

REFERENCE

Order F. No. L-12012/22/78-D.II.A, dated 25-4-1978 / 2-5-1978

of the Ministry of Labour, Government of India

This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 3rd day of October, 1978 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material Papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal K. K. Mundul, President, Corporation Bank Employees' Union, Bombay and U.P. Shet, Treasurer, Tamilnad Bank Employees' Federation, Madras for the Union and of Thiru M.R. Narayanaswami, an officer of the Employers' Federation of India, Bombay for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration this Tribunal made the following.

AWARD

This is an industrial dispute referred to this Tribunal for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Mangement of the Corporation Bank Limited, Mangalore and their workmen in the matter of additional sick leave.

(2) The following is the reference :—

"Whether the action of the management of the Corporation Bank Limited Mangalore in refusing additional sick leave to Shri A. Sankaran Nair, Attender Accounts Section, G.T. Branch of the Bank is legal land justified. If not, to what relief is the workman entitled ?"

(3) The Union filed a claim statement, wherein they state as follows : Thiru A. Sankaran Nair, the worker is an Attender in the Corporation Bank Branch at Madras. He joined the service of the bank on 23rd April, 1953 and continued to be in uninterrupted service till 1st July, 1954. Thereafter he continued in the permanent service of the bank in the same category and he applied for special sick leave. The Management by their letter to him granted leave 4 days of special sick leave Unavailed Casual Leave from 6th May, 1977 to 9th May, 1977) and for 16 days of loss of pay leave (from 10th May, 1977 to 25th May, 1977). The Management was granted only 4 days of special sick leave out of 20 days special sick leave applied for. Therefore he demanded that the balance of 16 days sick leave should be treated as special sick leave on half pay in that he had already completed 24 years of service and in terms of para 23, 29 of the Bipartite Settlement between Indian Banks Assiciation and All India Bank Employees Association. On 22nd April, 1977 the Management in a reply to Thiru A. Sankaran Nair stated that eligibility for additional sick leave would accrue only after completion of 24 years of service and in as much as the probation period of Sankaran Nair commenced from 1st July, 1954 he will not be eligible for additional sick leave for 16 days. Thiru A. Sankaran Nair requested the Bank to reconsider the matter, but the Bank rejected his claim. The matter in dispute is not merely confined to an Attender but is of vital interest of all the workmen employed by the Bank. The stand by the Management that the period of service to be computed from the date of confirmation for calculating the entire service is not correct. Hence this reference.

(4) A counter statement was filed by the Management, wherein they contend as follows: The Petitioner Thiru A. Sankaran Nair was working as a temporary peon in the G.T. Madras Branch with effect from 23rd April, 1953 and he was confirmed in the service of the Bank with effect from 1st July, 1954 in terms of office memorandum dated 17th July, 1954. The employee wanted the Bank to add the period of service worked as a temporary peon from 23rd April, 1953 till the date of his confirmation for calculating the entire length of service for entitlement of additional sick leave in terms of the provisions laid down at para 13.29 of the Bipartite Settlement. In terms of Bipartite Settlement he would become eligible for additional sick leave with effect from 1st July, 1978 when he completes 24 years of service and not with effect from 23-4-1977, tthe commencement of the period of service. In the past the similar issue came up for consideration before the Labour Appellate Tribunal of India and the Tribunal after considering the various provisions of the Bank Awards, has held that upon a proper interpretation of the Award the service of a workman for the purpose of sick leave is to be computed from the date on which he is confirmed. Therefore a Settlement on 8th November, 1973 by which it was agreed by the parties relating to other issues which were not settled were to be referred to Indian Banks' Association and All India Bank Employees' Association for discussion of the Settlement and they were prohibited from approaching this Tribunal for redressal of their grievances. Hence the claim is not maintainable before this Tribunal as this Court has no jurisdiction to try the issue.

(5) Though the Management has urged in the counter that this Tribunal has no jurisdiction to try the issue in view of the Settlement between parties dated 8th November, 1973, no argument was addressed by the learned counsel for the Management and he confined himself only to one issue, namely, whether the claim of the Petitioner for the additional sick leave is legal and justified.

(6) The issue in this case lies in the narrow campus, namely, whether for purpose of computing the period of service, the date of entry into service or the date of confirmation is to be taken into account.

(7) The following facts which are quite relevant to decide the issue are not disputed. The Petitioner Thiru A. Sankaran Nair entered as peon in the bank services on 23-4*1953 and he was confirmed on 17-7-1954. Ex, M-1 in the Memorandum dated 17-7-1954 confirming the services of Thiru A. Sankaran Nair as Peon. Ex. M-2 dated 7-8-1954 is an agreement between the Bank and Thiru A. Sankaran Nair. Ex.W-1 is the Bipartite settlement between the Indian Banks' Association and All India Bank Employees, Association which has been relied upon by the Union to support their contention. In the Bipartite Settlement, provision has been made for sick leave in paragraph 13.29 which runs as follows :

"An employee shall be granted sick leave at the rate of one month for each year of service subject to a maximum of 12 months during his entire service,

provided that where an employee has put in a service of over 24 years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of 24 years, subject to a maximum of three months of such additional sick leave."

Therefore the Court has to interpret what was the intention of the parties when an agreement was reached since it is quite silent about the question whether the period of 24 years has to be computed from the date of service or the date of confirmation. The Management relies upon Ex. M-3, the decision of the Labour Appellate Tribunal of India, Bombay in reference No. 1/56 between the workmen of the Bank of Behar Limited, Kanpur and the Bank of Behar Limited, Kanpur. It was contended on behalf of the Bank that the amount of year's sick leave which has been granted by the award begins to accumulate after the 1st April, 1953 and that the computation started from the very day on which an employee is confirmed in his appointment. It was held on a proper interpretation of the Award that the service of a workman is to be computed for the purpose of sick leave from the date on which he was confirmed. The above decision is in consonance with the intention for making provision for sick leave. In this context the Tribunal has to see the status of the workman till he is confirmed. He acts only temporarily before his confirmation and is not entitled to many privileges which he becomes entitled on the day when he is confirmed. Until his confirmation the Management has right to oust him from service and he cannot avail himself leave such as leave with pay during the time he is working temporarily. He attains full stature only after confirmation. He cannot compel the Management to recognize privileges during the period of temporary service which he can urge when he becomes a permanent employee. Sick leave is one such privilege and he gets that privilege of 12 months only after completion of 24 years of service. In view of the fact that the worker acting temporarily cannot claim any privilege as against the Management he cannot claim the privilege of additional sick leave during the time when he serves as a temporary workman. Therefore on purpose of computation for sick leave, the period for computation should be the date of confirmation and not the date of entry into service.

(8) Viewed in that light admittedly the Petitioner worker had not completed 24 years of service on the date of reference to this Tribunal though he had completed 24 years subsequently. As it is of vital importance to the services in the Bank I have to hold for computing special sick leave, the period of confirmation alone as relevant and the service should be computed from the date of confirmation.

(9) An Award is passed accordingly.

Dated. this 16th day of October, 1978.

(Sd) K. Selvaratnam

INDUSTRIAL TRIBUNAL

WITNESSES EXAMINED

For both sides : Nil.

DOCUMENTS MARKED

For workmen

Ex. W-1 Bipartite settlements between the Indian Banks Association and All India Bank Employees' Association. (book).

For Management.

Ex. M-1/17-7-54—Memorandum confirming the services of Thiru A. Sankaran Nair.

Ex. M-2/7-8-154—Service agreement between the Bank and Thiru A. Sankaran Nair.

Ex. M-3/13-7-56—Decision of the Labour Appellate Tribunal of India Bombay in Reference No. 1/56,

(Sd) K. SELVARATNAM, Presiding Officer

(No. L-12012/22/78-D.II.A)

R. P. NARULA, Under Secy.

New Delhi, the 4th November, 1978

S.O. .—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Shri Bhagwan Sahiji, Mine Owner, Karauli and Radhey Shyamji Sharma, Keladevi and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th October, 1978.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI.

I. D. No. 197 of 1977

In re :

Workmen employed in Kariya and Churiya Sand Stone Mines in Tehsil Karuli, District Sawaimadhopur.

Workmen employed in Deviji Plot No. 3,
Sand stone Mine in Tehsil Karuli,
District Sawaimadhopur. Petitioners

Versus

1. Shri Bhagwan Sahai Sharma,
Mint Owner, Karuli, Sawaimadhopur.

2. Shri Radhey Shyamji Sharma,
Mine, Owner, Kaladevi,
District Sawaimadhopur. Respondents.

AWARD

The Central Government as appropriate Government made reference u/s 10 of the I. D. Act, 1947 vide the order No. L-29011/23/77-D.III.B dated the 19th September, 1977 in the following terms :

"Whether the demand of workmen employed in Kariya and Churiya and Stone mines in Tehsil Karuli, District Sawaimadhopur of Shri Bhagwan Sahai Sharma, Mine, Karauli for payment of Bonus @ 20 per cent for the A/c years 1974-1975 and 1975-76 and of workmen employed in Devji Plot No. 3 Sand Stone Mine in Tehsil Karauli District Sawaimadhopur of Shri Radhey Shyamji Sharma, Kaladevi for payment of Bonus @ 20 per cent of wages for the A/c years 1972-73, 1973-74, 1974-75 and 1975-76 is justified? If not to what relief, if any, are the workmen entitled to."

2. On receipt of the reference it was ordered to be registered and requisite notices were sent to the parties. However before any other proceedings could take place in the matter a settlement Ex. S/1 was filed by the workmen and in pursuance thereof statement of Shri Mahabir Parshad Sharma, the representative of the workmen was recorded in which it is stated by him parties have settled the dispute vide Ex. S/1 and a no dispute award be made in this matter.'.

3. In view of the above statement and in view of Ex. S/1 a no dispute award is hereby returned in this reference. Parties are left to bear their own costs.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : the 18th September, 1978.
27th Bhadra, 1900.

[No. L-29011/23/77-D.III.B]

New Delhi, the 6th November, 1978

S.O. 3334.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Visvesvaraya Iron and Steel Limited, Bhadravati, and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th October, 1978.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN

KARNATAKA BANGALORE

Dated the 25th October, 1978

PRESENT

Central Reference No. 2 of 1978

I PARTY.		II PARTY.
Workmen represented by the General Secretary, MISL Mines Employees' Association, Room No. 1, Trainees Block-10, New Colony, Bhadravati, Karnataka.	—Vs—	The General Manager The Visvesvaraya Iron & Steel Ltd., Bhadravati-577301.

APPEARANCES

For the I Party—Sri M. Selvarajan, General Secretary, MISL Mines Employees' Association, Bhadravati.

For the II Party.—Sri B. S. Satyanarayana. Law Officer, VISL, Bhadravati.

REFERENCE

(Government Order No. L-26012/4/77-D.II.B dated the 31-5-1978)

AWARD

As per Order No. L-26012/4/77-D.III.B. dated 31-5-1978 issued in exercise of its powers under Section 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the transfer of Shri K. Ajjappa, Foreman, Kemmangudi Mines and Treasurer of MISL Mines Employees' Association, from Bhadigund Mines to Kemmangudi Mines amounts to victimisation? If so to what relief is the said workman entitled?"

2. On receipt of the reference, notice was taken out to both the parties. The II Party filed its objection statement in the first instance raising the contention that since the employee cannot challenge the managements right to tranfer from one department to another department, the dispute cannot be termed as an industrial dispute. The II Party also urged that the employee was working as a Foreman in the supervisory capacity drawing the wages of Rs. 500 per month and is not a workman as defined under Section 2(s) of the Industrial Disputes Act. The reference is therefore not valid on this ground also. The transfer was effected in the interest of the management and without any malafide intention.

3. Since the I Party was absent when the II Party filed its objection statement, a copy of the said statement was ordered to be sent to the I Party along with the intimation that the case is posted for I Party's claim statement. The I Party remained absent on the subsequent 3 days of hearing though it requested by post for extension of time or filing of its claim statement.

4. When the proceedings were taken up on the adjourned date (17-10-1978) M. Salvarajan, the Secretary of the I Party, and B. S. Satyanarayana, the II Party's Law Officer, were present. M. Selvarajan stated that the workman mentioned in the order of reference has since been transferred as per his request from Kemmangundi Mines to another mines, namely, Umblebyle Mines, the reference is not pressed, relief under the reference having been granted, and filed a memo accordingly (vide copy annexed hereto). In the light of the memo filed by the I Party, the reference stands disposed of. An award is passed accordingly.

(Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me).

Dated : 25-10-1978.

F. L. F. ALVARES, Presiding Officer.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER INDUSTRIAL TRIBUNAL BANGALORE

Central Reference No. 2 of 1978

Workmen represented by the General Secretary, MISL. Mines Employees Association : I Party.

Versus

The General Manager, Visvesvaraya Iron and Steel Limited : II Party.

MEMO OF COMPROMISE

In the above reference the I party Shri Ajjappa Foreman is transferred to Umblebyle Mines from Kemmana-Gundi Mines as per his request. In view of this fact the above reference is not pressed as the relief under the reference is granted and both the parties pray for an Award on the above terms.

Sd/-
President,
I Party, Gl. Secy.

Sd/-
II Party, General Manager
Visvesvanaga Iron and Steel Ltd. Bhadravati

Sd/-
Manager, Industrial Tribunal, Bangalore

[No. L-26012/4/77-D.III.B.]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

Dated : 14-10-1978.
Bhadravati.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978